

ई-कॉमर्स का जटिल परदृश्य

प्रलम्बिस् के लयिः

[वशिव वयापार संगठन](#), [ई-कॉमर्स](#), [करपिटोकरेंसी](#), [यूनफाइड पेमेंटस इंटरफेस \(UPI\)](#), [गवरनमेंट ई-मार्केटप्लेस\(GeM\)](#), [भारतनेट परयोजना](#), [ओपन नेटवरक फॉर डजिटल कॉमर्स \(ONDC\)](#), [राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति](#), [उपभोक्ता संरक्षण \(ई-कॉमर्स\) नयिम, 2020](#)

मेन्स के लयिः

ई-कॉमर्स और संबंघति मुद्दों द्वारा प्रदान कयि गए लाभ

[स्रोतः इकॉनोमिक टाइम्स](#)

चर्चा में कयों?

जनिवा में वशिव वयापार संगठन (WTO) की हालयिा बैठक में भारत ने वस्तुओं और सेवाओं में ई-कॉमर्स वयापार की स्पष्ट परभिषा की कमी पर चतिा जताई है।

- सटीक चतिरण के अभाव के कारण वकिसति और वकिसशील सदस्य देशों के बीच वरिधाभासी वचिार उत्पन्न हो गए हैं, वशिषकर सीमा शुल्क लगाने के संबंघ में।

ई-कॉमर्स से संबंघति वविाद के प्राथमकि कारकः

- ई-कॉमर्स में वयाख्यातमक भनिनताः वस्तु बनाम सेवाएँ
 - [वकिसति](#) और [वकिसशील देशों](#) की ई-कॉमर्स की वयाख्या में भनिनता है, वशिषकर वस्तुओं और सेवाओं पर सीमा शुल्क लगाने के संदरभ में।
 - इस चुनौती का उदाहरण [नेटफ्लिक्स](#) जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं के मामले में देखा जाता है, जहाँ कंटेंट (एक उत्पाद) सेवा सदस्यता के माध्यम से वतिरति की जाती है।
 - इस भनिनता से WTO ढाँचे के भीतर स्पष्ट नीतियों का नरिमाण और अधकि जटलि हो गया है।
- सीमा शुल्क से संबंघति अनशिचतिताएँ:
 - WTO के सदस्य वर्ष 1998 से [इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमशिन](#) पर सीमा शुल्क लगाने के संबंघ में अधसिथगन की अवधा को समय-समय पर बढ़ाते रहे हैं। इसे आखरि बार [12वें मंत्रसितरीय सममेलन](#) के दौरान बढ़ाया गया था।
 - कति सेवाओं में ई-कॉमर्स वयापार के लयि एक परभिषाति ढाँचे के न होने के परणामस्वरुप अनशिचतिताएँ उत्पन्न होती हैं, जसिसे समान अवसर बनाए रखने को लेकर चतिाएँ बढ़ जाती हैं।
 - भारत संबद्ध वषिय पर सटीक परभिषा की आवशयकता पर प्रकाश डालता है तथावशिष रूप से [डजिटल वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर स्पष्ट करने की आवशयकता पर ज़ोर देता है](#) कयोंकि सीमा शुल्क पहले से ही वस्तुओं पर लगाए जाते हैं कति सेवाओं पर नहीं।

नोटः वकिसति देश [शुल्क-मुक्त वातावरण](#) का समर्थन करते हैं, जबकि वकिसशील देश घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और [सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम \(MSME\)](#) के वकिस का समर्थन करने के उद्देश्य से [शुल्क लगाने के लयि](#) नीतगित स्थान चाहते हैं।

- **करपिटोकरेंसीः ई-कॉमर्स वयवधानः**
 - ग्लोबल ट्रेड रसिर्च इनशिष्टि (GTRI) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि [करपिटोकरेंसी](#) की वृद्धि मौजूदा WTO ई-कॉमर्स ढाँचे के लयि एक चुनौती है, जसिसे उन्हें [इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमशिन](#) के रूप में वर्गीकृत करने के लयि चर्चा की तत्काल आवशयकता है।

ई-कॉमर्सः

■ परचिय:

- वशिव व्यापार संगठन ई-कॉमर्स को वस्तुओं और सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, वतारण, बकिरी या डलिवरी करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में परभाषति करता है ।
- इसमें डजिटल रूप से प्रसारति कतिाबें, संगीत और वीडियो जैसे उत्पाद शामिल हैं ।

■ ई-कॉमर्स द्वारा प्रदत्त लाभ:

- सुवधि और अभगिम: इनसे ग्राहक उत्पादों और सेवाओं को अदवतीय सुवधि एवं अभगिम प्रदान करते हुए, कभी भी, कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं ।
- डेटा-संचालति अंतरदृष्टि: उपभोक्ता डेटा तक अभगिम, व्यवसायों के ग्राहक व्यवहार, प्राथमकिताओं और रुझानों को समझने के लिये मूल्यवान अंतरदृष्टि प्रदान करती है, जसिसे लक्षति वपिणन एवं बेहतर ग्राहक अनुभव मलिता है ।
- वविधि उत्पाद पेशकश: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ही स्थान पर उत्पादों और सेवाओं की एक वसितृत शृंखला पेश करते हैं, जसिसे ग्राहकों को वभिनि प्रकार के उत्पादों के वकिल्पो में आसानी से तुलना एवं चयन करने की सुवधि मलिती है ।
- सुवधिजनक भुगतान वकिल्प: वर्तमान में कई भुगतान गेटवे और वकिल्प उपलब्ध हैं जो व्यवसायों तथा ग्राहकों दोनों के लिये लेनदेन में सरलता एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं ।
- 24/7 पहुँच: भौतिक दुकानों के वपिरीत, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 24/7 परचालन में रहते हैं, जो पूरे वशिव में ग्राहकों के लिये उत्पादों और सेवाओं तक नरितर पहुँच प्रदान करते हैं ।
- वैश्वकि पहुँच: ये प्लेटफॉर्म व्यवसायों के भौतिक स्थानों तक सीमति हुए बना वशिवव्यापी बाज़ार तक पहुँचने में सक्षम बनाकर व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँच प्रदान करता है ।

ई-कॉमर्स से संबंधति भारत सरकार की पहल:

- [यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस \(UPI\)](#)
- [गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस\(GeM\)](#)
- [भारतनेट परयोजना](#)
- [ओपन नेटवरक फॉर डजिटल कॉमर्स \(ONDC\)](#)
- [राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति](#)
- [उपभोक्ता सरकषण \(ई-कॉमर्स\) नयिम, 2020](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/complex-landscape-of-e-commerce>

